ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Media Bite **11 March, 2021**

Smt. Supriya Shrinate, Spokesperson, AICC addressed the media at AICC Hdqrs, today.

श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज महाशिवरात्रि की आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव सद्बुद्धि दें सरकार में बैठे लोगों को और हमारी महिलाओं को सुरक्षित बनाए। मैं यही आशा करती हूं, आज दो मामले हैं। पहला मामला मेरे गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, तो पहले उस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बड़े ताम-झाम से महिला दिवस मनाया गया था। खैर, मेरा तो ये मानना है कि एक ही दिन महिलाओं का नहीं होता है, ये पूरा साल हमारा है और हमारी शक्ति को कम आंकना गलत होगा। खैर, महिला दिवस मनाया गया, नारी शक्ति का आह्वान हुआ और उसके बाद, एक के बाद एक खबर जो उत्तर प्रदेश से महिलाओं के दमन की, बढ़ते हुए अपराध की आती है, वो सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

उन्नाव, शाहजहांपुर, हाथरस, लखीमपुर, बाराबंकी और अब कानपुर। एक 13 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है। उसके पिता एफआईआर करते हैं और उन्हीं को कुचल कर मार दिया जाता है। आपको याद है, उन्नाव में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा क्यों होता है? पहले तो पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कर दो और फिर उसको थोड़ा बहुत हक दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला हो, उसको भी मार डालो? हर साक्ष्य खत्म कर दो और ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके पिता जी उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी हैं। तो ना पैरवी होगी, ना दोषियों को सजा मिलेगी और महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ता चला जाएगा।

एक 13 साल की बच्ची का गैंग रेप अपने आप मे दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन योगी जी के मुँह से एक शब्द नहीं फूटता है। अमित शाह जी के मुँह पर चुप्पी है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप रहते हैं और इन सब लोगों की चुप्पी निंदनीय ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है, इनके आडंबर और ढोंग पर, जो महिलाओं के नाम पर नारी शक्ति इत्यादि नारों से रचे जाते हैं और इनकी चुप्पी जो है, जिसे मैं सुई बटे सन्नाटा कहती हूं, Pin drop silence. वो महिला सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। योगी जी के पास वक्त है मालदा जाकर वोट मांगने का। वो बंगाल जाकर कहते हैं कि अपराध मुक्त हो जाएगा बंगाल। आपकी नाक के नीचे जो अपराध हो रहा है, आपकी नाक के नीचे जो अराजकता है, उससे आप उत्तर प्रदेश को कब मुक्त करिएगा?

और ये सच है कि ये एक स्क्रिप्ट है और ये बार-बार रिपीट होती है। पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है। उसके बाद उसको छुपाने के, उनके साक्ष्य मिटाने की कोशिश होती है। कुछ नहीं है तो जो पैरवी करने वाला भाई या बाप है, उन्हीं को मार दिया जाता है। पूरी की पूरी भक्त मंडली, सूचना सलाहकारों की मंडली, आला पुलिस अधिकारी, गवर्मेंट सब लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, महिला के पहले तो प्रूव करने में कि रेप हुआ ही नहीं है और फिर उसका चरित्र हनन करने में, उसका करेक्टर एसेसिनेशन होता है और उसके बाद जब ये सब होने के बावजूद फिर भी साबित हो जाता है कि नहीं, रेप हुआ है, तो मुँह में दही जम जाती है। क्या हुआ था हाथरस में, वही कानपुर में हो रहा है। एक भी शब्द हमें अभी तक सरकार से सुनाई नहीं दिया है।

मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का जो मूल है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार से ही निकलता है। भाजपा ने 2017 में 312 सीट जीती थीं। उनके 114 विधायकों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 82 के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जैसे कि रेप और मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं।

खैर, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के खिलाफ अपराध के इस बढ़ते ग्राफ को देखकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक शब्द तो बोलिए, एक शब्द नहीं बोलते हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी या तो निर्वाचित सरकारों को गिराने में या ध्रुवीकरण करने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है महिला सुरक्षा पर बोलने का। अगर दिल नहीं दहल रहा है तो मोदी जी एक शब्द तो बोल दीजिए, इसको संज्ञान में तो ले लीजिए, ये बड़ा मामला है।

लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख उनकी चुप्पी पर होता है, जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं एवं बाल और महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। आपने क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली है, क्यों मुँह में दही जमा लिया है? क्या सत्ता का सुख और लोभ हमारी महिलाओं की पीड़ा, उनके दर्द, उनकी सुरक्षा से ज्यादा बढ़कर है? मेरा सिर्फ अपना मानना है कि इस बेटी के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए।

हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जिन दोषियों ने ये कुकृत्य किया है, उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले और जिन लोगों ने एक पिता की हत्या की है। साक्ष्य और विटनेस और पैरवीकार करने वालों को रास्ते से हटाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। कभी तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार का मरा हुआ जमीर जागेगा और उसी दिन महिलाओं की सुरक्षा का मामला शायद उनके लिए प्राथमिकता बनेगा।

Smt. Supriya Shrinate said- Three days back, we celebrated International Women's day with much fanfare and today again, a very disturbing news from Kanpur, first the rape of a 13 year old girl, which in itself should shake the collective consciousness of our society, but, what we see after that, is even more shameful, even more disturbing. Her father is crushed by a moving vehicle and this is a script that gets repeated in Uttar Pradesh. This is the same thing that had happened in Unnao. The victim was intimidated, to intimidate her family, her family members were killed one by one to remove evidence to remove proof and finally Mr. Sengar was found guilty and this is exactly what has happened in UP.

It is no surprise to me that the main accused is the son of a UP Police Officer and the abject silence of Yogi Adityanath or Shri Amit Shah or Mr. Modi is very-very questionable. They are conspicuous by their silence. Yogi Adityanath has the time to go and campaign in West Bengal and talk about crime against women, what about your own track record, Sir? What is happening in UP and who is going to be responsible for that, right under your nose? Your information officers, your senior police officials, your MLAs, your Ministers, their first attempt is to deny rape; and when they failed to do so, they start assassinating the character of victim herself.

Instances after instances, Unnao, Hathras, Barabanki, Shahjahanpur, the kind of political patriotism that is offered is perhaps the reason for crimes like these and which is why, out of 312 elected BJP MLAs in 2017, 114 of them face criminal charges and 82 of them, nearly 40 per cent face grave criminal charges like rape and murder. Can we even expect that people like these will ensure justice? We demand that given the moral compass of Yogi Adityanath, which has completely lost, he will take into cognizance, he will break his silence and he should ideally quit his position.

We hope, Shri Amit Shah, who is perhaps too busy toppling elected Governments and also polarising polls and poll bound states will take this into cognisance. We hope, Mr Modi will find this worthy of a mention, but, what disturbs me the most is that the woman MP from UP, who also is the Union Minister for Women and Child Development is absolutely silent on this, not a word from her. I hope, she will break her silence because security of women is not an irrelevant issue.

We demand that the family be duly compensated. We demand a judicial inquiry and we demand that the insensitive Government wakes up and owns up its moral responsibility. This is not just a gang rape; this is murder of the father, playing with evidence in some sense, also annihilating those, who can fight for her rights against in justice.

एक और मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा है। एक मामला सामने आया है और उस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं सरकार की बखियां उधेड़ कर रख दी है। जो सरकार और प्रधानमंत्री, 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, आज वो एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हां, मैं स्कैनिया (Scania) के घोटाले की बात कर रही हूं। स्कैनडिनवियन (Scandinavian) रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि केन्द्र सरकार को और कुछ प्रांत की सरकारों को घूस दी गई थी, बस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इसलिए मैं मानती हूं कि ये घोटालों की सरकार है। क्योंकि जब कोई घोटाला सामने आता है, तो पूरी तरह से चुप्पी आ जाती है। मैं बार-बार कहती हूं, pin drop silence, सुई बटे सन्नाटा और ये बड़ा मामला है। हम जानना चाहते हैं कि ये किस केन्द्रीय मंत्री की बात हो रही है, क्योंकि एक केन्द्रीय मंत्री के ऑफिस से एक अदना सा स्टेटमेंट रिलीज हुआ है? लेकिन साक्ष्य दिखाते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, वो पूरी तरह से व्यापक था, पूरी तरह से व्याप्त था। जो-जो लोग उस कंपनी से मिल रहे थे, उसकी अभी

हम आपके साथ तस्वीरें साझा करेंगे, क्योंकि बताना जरुरी है कि जो जग जाहिर था भ्रष्टाचार, उसमें कौन-कौन लिप्त था? कौन सी वो प्रांतीय सरकारें थी, केन्द्र सरकार ने उस पर क्या एक्शन लेने की कोशिश की? क्यों चुप हैं आज मोदी जी? आप तो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'। आपने तो कुछ खाने से छोड़ा ही नहीं है। ये एक सत्य है। और ये भी सत्य है कि सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिसने रिश्वत दी, वो स्वीकार कर रहा है। रिपोर्ट उस कंट्री की स्वीकार कर रही है कि रिश्वत दी गई। जिसने रिश्वत ली, वो मुँह में दही जमाए बैठा है, वो एक शब्द नहीं कहना चाहता है। तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक मनी, पब्लिक एकाउंटेबिलिटी ये सब चीजें शामिल हैं और सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।

मैं आपके साथ कुछ साक्ष्य और कुछ तस्वीरें जरुर साझा करना चाहती हूं।

ये कुछ तस्वीरें हैं, इसमें आपको सरकार के तमाम मंत्री, अगर आप लोग जूम इन कर लें, तो मैं अनुगृहित रहूंगी। सरकार के तमाम मंत्री, उस कंपनी के साथ सांझा हो रहे हैं। (तस्वीर दिखाते हुए सुश्री श्रीनेत ने कहा) ये प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जैसे कि उनकी शैली रहती है। ये स्कैनिया के सीईओ हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री महोदय जी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान की पूर्व चीफ मिनिस्टर दिख रही हैं। यहाँ पर आपको रोड़ एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री नितिन गड़करी जी दिख रहे हैं। अगर आप और आगे बढ़िएगा, तो फिर से प्रधानमंत्री जी हैं। यहाँ पर आपको कानून मंत्री, रविशंकर प्रसाद जी दिख रहे हैं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़बोले हैं, जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे कि रिश्वत किसने ली है? और जब कंपनी कहती है कि रिश्वत दी गई है, तो क्या एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की? रिश्वत किसने ली है, इसके बारे में कौन बताएगा हमें? ये तस्वीर नितिन गड़करी जी की है। मैं वापस जाना चाहूंगी, जो तस्वीरें खुलकर सामने आई हैं, मोदी जी की, प्रांतीय सरकारों की, सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री की, जिस तरह का दोषारोपण हुआ है। ये एक गंभीर मामला है और गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिश्वत का ये फेर लंबा था। रिश्वत का ये फेर इसलिए लंबा था, क्योंकि इसमें रिश्वत दी गई है, कंपनी ने ये स्वीकारा है और सरकार ने अभी तक इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।

हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की ज्यूडिशियल जांच हो। एक अदना सा स्टेटमेंट किसी मंत्री के ऑफिस से स्वीकार्य नहीं है। ये पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी, ये पब्लिक लाइफ में एकाउंटेबिलिटी, पब्लिक लाइफ में स्वच्छता का मामला है। ये आक्षेप सीधा-सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है और इस पर वो चुप्पी नहीं रख सकते हैं।

The reports of the bus contract scam are indeed very-very disturbing. The Scandinavian Government reports point a finger at India's Central Government, various Ministers, various state Governments and even then the Prime Minister's office is absolutely silent on this. The same Prime Minister, who used to speak about probity in public life is today forced to be silent. He does not even want to talk about this. We get an obscured statement from the office of a Minister. This is a finger pointing at the highest level of the Government. I will produce some proof here. These are pictures of various ministers including the Prime Minister

with the management of Scania, if you actually go on to see this is the Prime Minister with their CEO various pictures there. There are various pictures with Mr. Gadkari, There are also pictures with Vasundhara Raje Ji, who was then the Rajasthan Chief Minister. Here is Mr. Gadkari Ji, the Surface Transport Minister then, the Prime Minister again, what you actually see is also India's Law Minister, the IT and Telecom Minister, Ravi Shankar Prasad Ji, at some point in time somebody in this Government will have to explain what was happening here. They will have to answer a very basic question, who is responsible for this? Their absolute silence, their conspicuous silence cannot be ignored and their absolute conspicuous silence is on account of this Government's complicity. There is no other reason, why they are silent. Look at these pictures and they tell you a tail of a lot of proximity. They tell you a tail of lack of accountability.

We demand that there will be a judicial inquiry into this. We demand that the Government of India take this into cognisance and issue a statement clarifying its position, because this is the strange case, where somebody who has offered the bribe, has accepted that a bribe has been offered, but, the bribe has been received by a certain section, who are absolutely quite and this goes all the way up to the Prime Minister's office, because he was involved with the various contracts and various signing and he is a part of all of these meetings.

We demand an inquiry into this and we hope that the Government will take this into cognisance and not brush it under the carpet just like many other scams in its regime have been brushed aside.

एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती श्रीनेत ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है, ये स्कैनडिनवियन की प्रेस ने स्कैनडिनवियन गवर्मेंट के सामने प्रस्तुत की है। जो साक्ष्य भी हम बता रहे हैं, जो आपने बसों के नंबर दिए हैं, ये वहीं से आए हैं। मैं उस रिपोर्ट को क्यों कोट करुं, क्योंकि वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक रुप से अवेलेबल है। जहाँ तक आपने नितिन गड़करी जी की बात है, हाँ, क्योंकि वो मुख्यत: मंत्री हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के, उनको तो जवाब देने की जरुरत है ही। लेकिन क्या इससे आप मोदी जी को बक्श देंगे? क्या रविशंकर प्रसाद जी, क्या उनके वेरियस मुख्यमंत्री चुप बैठेंगें? हां, नितिन गड़करी जी को जवाब देना पड़ेगा और उनके ऑफिस से एक अदना सा स्टेटमेंट जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन हमने आपको साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से इंडियन गवर्मेंट के आला अधिकारी, आला मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी भी इस पूरी संरचना का हिस्सा थे। और अगर ऐसे मामले में मोदी जी की तस्वीरें सामने आई हैं, स्कैनिया के सीईओ के साथ, तो वो एक्सप्लेन तो करें कि क्या बातचीत हो रही थी? क्योंकि जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि केन्द्र सरकार को, राज्य सरकारों को घूस दी गई। एक कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि उसने घूस दी, लेकिन विरोधाभास ये है कि जिसको घूस दी गई, वो चुप बैठा हुआ है, उसने मुँह पर पट्टी बांधी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते हर व्यक्ति को ईमानदारी से आगे आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देना चाहिए और इसको फिर से जो कॉरपेट के नीचे ब्रश कर दिया जाता है। इसको हर तरह से हटा दिया जाता है मामला, धीमे से उसको गायब कर दिया जाता है। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ का मामला है, इसकी उंगली सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक उठी है।

बढ़ती महंगाई पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सुश्री श्रीनेत ने कहा कि मैं खुश हूं कि आपने मुद्दे की बात की। एडिबल ऑयल की कीमत 95 रुपए होती थी, अब 150 रुपए में मिल रहा है। लेकिन इसके

बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है और मैं आज मीडिया में होने के नाते भी थोड़ा सा मीडिया को खरी-खोटी सुनाऊंगी और इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि जब हम भी मीडिया में होते थे, तो हम बढ़ती कीमतों पर बड़ी हाय तौबा मचाते थे। आज वही मीडिया के एडिटर न्यूज चैनल पर बैठकर या एडिटोरियल लिखकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर महंगाई है। आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। तो जब पहले महंगाई का आप विरोध करते थे और भाजपा भी करती थी, तो क्या आप तब देशद्रोह कर रहे थे, आप राष्ट्रद्रोह कर रहे थे? महंगाई सबसे बड़ा अभिशाप है, महंगाई सबसे बड़ा पाप है। आप एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं। एक खबर आई है, एक समाचार पत्र में कि एफएमसीजी कंपनियाँ, जो कंपनियाँ साबुन, तेल, शैंपू, दांत का मंजन इत्यादि बनाती हैं, उन कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने शुरु कर दिए हैं, क्योंकि रॉ मैटेरियल के प्राईस बढ़ गए हैं और एफएमसीजी का दाम तब बढ़ता है जब महंगाई सर के ऊपर से गुजरने लगती है और एफएमसीजी ने, क्योंकि उनका रॉ मैटिरियल का कोस्ट इतना बढ़ गया है, वो कहते हैं, विवश है दाम बढ़ाने के लिए और एफएमसीजी का बढ़ता दाम हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, जो मंजन करता है इस देश में। वो देश का सबसे अमीर आदमी है और उस पंक्ति में, गरीबों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा गरीब व्यक्ति है। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। 100 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। चुनाव आएंगे तो दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे। चुनाव चले जाएंगे तो आपकी कमर फिर तोड़ी जाएगी। एलपीजी का सिलेंडर 225 रुपए बढ़ जाता है, 6 बार दाम बढाए गए हैं तीन महीने में। किस चीज का बदला आप देशवासियों से ले रहे हैं? ये देशवासी आपके कुप्रबंधन के बावजूद कोरोना में आपके साथ खड़े रहे। 2 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई, फिर भी आपका इस देश ने साथ दिया, आपका हाथ पकड़ा। आप देश से किस चीज का बदला ले रहे हैं? अगर वाकई में आप देश का भला चाहते हैं तो पेट्रोल,डीजल और एलपीजी की कीमतों को घटाइए, जब ये कीमतें घटेंगी, अपने आप एफएमसीजी खाद्य पदार्थों की कीमतें भी घटेगी। आप रीडिंग ले लीजिए, जो लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र ट्रेक करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन तो जबरदस्त बढ़ ही रहा है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जो फूड एंड फ्यूल को छोड़कर होता है, वो साढ़े 6 प्रतिशत आया जनवरी में और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी भयावह सिचुएशन होने वाली है। आरबीआई ने दबी जुबान में इसका उल्लेख भी किया है। तो मुझे लगता है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई वही डायन है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में वो डार्लिंग बन चुकी है, डायन नहीं है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC